समाचार विज्ञप्ति

नियुक्तियों में संवैधानिक परिवर्तन के लिए मोशन

30 मार्च, 2026

अल्बर्टा सरकार एक प्रस्ताव पेश करेगी जिसमें संवैधानिक संशोधनों की मांग की जाएगी, जिससे प्रांत सरकार को उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के संबंध में अपनी बात रखने का अधिकार मिल सके।

संविधान अधिनियम, 1867 की धारा 96 के तहत, संघीय सरकार प्रांतीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, भले ही प्रांत इन अदालतों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हों। अल्बर्टा का प्रस्ताव कहता है कि इस ढांचे में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि प्रांत के पास न्यायधीशों का चयन करने के लिए औपचारिक भूमिका हो जो कि अल्बर्टावासियों की सेवा करते हैं।

यह प्रस्ताव यदि विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है, तो यह कैनेडा के संविधान में संशोधन की मांग करेगा। किसी भी परिवर्तन के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होगी। अल्बर्टा संसद में सभी दलों से अपील कर रहा है कि वह आवश्यक संवैधानिक संशोधन को पेश करें और पारित करवाएं।

प्रस्तावित दृष्टिकोण के अंतर्गत, अल्बर्टा की उच्च न्यायालयों में नियुक्तियाँ अल्बर्टा द्वारा अनुशंसित और अनुमोदित उम्मीदवारों में से की जाएँगी, जिससे प्रांत को चयन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भूमिका मिलेगी। यह दृष्टिकोण न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है और न्यायिक नियुक्तियों में एक स्पष्ट प्रांतीय आवाज सुनिश्चित करते हुए न्याय प्रशासन में अल्बर्टा की भूमिका को मजबूत करता है।

"अल्बर्टा इस प्रांत में न्याय कैसे दिया जाता है, इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में इसकी सीधी भूमिका नहीं है। वे अदालतें हर दिन अल्बर्टा निवासीयों की सेवा करती हैं, और उस प्रणाली को प्रशासित करने वाले प्रांत की भूमिका होनी चाहिए कि इसमें किसे नियुक्त किया जाए। यह प्रस्ताव उस अंतर को संबोधित करता है, जनता के विश्वास को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इस प्रांत में न्याय कैसे दिया जाता है, इसमें अल्बर्टा की स्पष्ट भूमिका है।

डेनियल स्मिथ, प्रीमियर

कनाडा संघीय प्रणालियों के बीच एक अपवाद है, जहां कि तुलनीय देश राज्य या प्रांतीय सरकारों को न्यायिक नियुक्तियों में सीधी भूमिका देते हैं। वर्तमान में न्यायिक नियुक्तियां न्यायिक सलाहकार समितियों के माध्यम से की जाती हैं, जो आवेदकों का आकलन और स्क्रीनिंग करती हैं और संघीय सरकार को गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रदान करती हैं। वर्तमान प्रक्रिया प्रांतीय सरकारों को न्यायाधीशों की नियुक्ति में सार्थक भूमिका नहीं देती है।

"प्रांतों को यह तय करने में सीधी आवाज की जरूरत है कि उनकी अदालतों में बैठने के लिए सबसे उपयुक्त कौन है। यह दृष्टिकोण न्यायिक नियुक्तियों को कैसे किया जाता है, इस पर अधिक संतुलन लाएगा और न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करते हुए अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया का समर्थन करेगा।

Classification: Public

समाचार विज्ञप्ति

मिक्की अमेरी, न्याय मंत्री और अटॉर्नी जनरल

अल्बर्टा के प्रीमियर डेनिएल स्मिथ ने ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड, क्यूबेक प्रीमियर फ्रांस्वा लगो और सस्केचेवान प्रीमियर स्कॉट मो के साथ प्रधान मंत्री मार्क कार्नी को एक संयुक्त पत्र लिखा, जिसमें उच्च अदालतों, अपील की अदालतों और कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायाधीशों को चुनने के लिए एक सार्थक और सहयोगी प्रक्रिया का आह्वान किया गया।

यह पहल अल्बर्टा नेक्स्ट पैनल की प्रतिक्रिया पर आधारित है, जहां अल्बर्टन्स ने न्यायिक नियुक्तियों में एक मजबूत प्रांतीय भूमिका का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अदालतें अल्बर्टा के समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को दर्शाती हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- *संविधान अधिनियम, 1867* की धारा 96 के तहत गवर्नर जनरल को अल्बर्टा के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है।
- यदि पारित हो जाता है, तो प्रस्ताव संवैधानिक संशोधन के लिए अनुरोध करेगा। कानून बनने से पहले इस प्रकार के किसी भी संशोधन को घोषित किए जाने में अल्बर्टा की विधान सभा और संसद की मंजूरी आवश्यक होगी।
- वर्तमान में उच्च न्यायालय न्यायिक नियुक्तियां एक निर्णय न्यायिक सलाहकार समितियों के माध्यम से लिए जाती हैं, जो आवेदकों का मूल्यांकन और जांच करती हैं और संघीय सरकार को गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रदान करती हैं।

संबंधित जनकारी

- अल्बर्टा नेक्स्ट पैनल की सिफारिशें

संबंधित समाचार

- न्यायिक नियुक्तियों में सुधार के लिए प्रांत एकजुट हुए (24 मार्च, 2026)
- अलबर्टा में संघीय न्यायिक नियुक्तियां : प्रीमियर स्मिथ और मंत्री अमेरी (3 फरवरी, 2026)

मल्टीमीडिया

- न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखें